Rashtriya Sahara - 28- January-2024

ग्रामीण विकास

भारत डोगरा

नल से उत्साह मगर जल संरक्षण जरूरी

निवाड़ी ब्लॉक और जिले के गांव मजरा मकरा (मध्य प्रदेश) के लोग बहुत खुश हैं कि वहां के नलों में पानी आ गया है। उन्होंने बताया कि घर में नल का पानी आ जाए तो जिंदगी बहुत हद तक बदल जाती है। उनके गांव में पहले दो किमी. दूर पानी लेने जाना पड़ता था जहां खेत की सिंचाई वाले कुएं से पानी लाते थे। वह पूरी तरह साफ नहीं होता था। गांव में एक ही हैंडपंप ठीक से पानी दे रहा था और उस पर बहुत लाइन लगती थी। दिन में कितने ही चक्कर पानी लाने के लिए लगते थे। परिवार के एक सदस्य को तो इसी कार्य में अपना अधिक समय लगाना पड़ता था। पानी लाने का अधिक बोझ महिलाओं पर था पर अब कई महीनों से दिन में लगभग 40 मिनट पानी नल में आता था, जिससे जरूरत लायक पानी आ जाता है। पशुओं को पानी अब भी प्रायः कुएं या तालाब से ही पिलाया जाता है।

पहले स्कूल के बच्चों को भी पानी की बहुत कठिनाई थी। अब बच्चों को प्यास बुझाने में कठिनाई नहीं है। शौचालयों के लिए भी पानी उपलब्ध है और इस कारण उनका उपयोग भी बढ़ा है। अनेक गांवों में घर-घर नल का पानी पहुंचने से खुशी की लहर है, पर यदि गांव समुदाय में जागरूकता हो तो इस स्थिति को और बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ ऐसी ही भूमिका निभाई है निवाड़ी ब्लॉक और जिले के राजापुर गांव में परमार्थ संस्था के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। यहां आसपास के कुछ गांवों के नलों में पानी आ गया पर यहां नहीं आया तो यहां के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मिलकर बाधाओं को दूर किया ताकि गांव के नलों में शीघ्र पानी आ सके। कुछ घरों के भीतर नल लगाने के स्थान पर इन्हें बाहर ही लगा दिया। ऐसे कुछ नल चुरा लिए गए और कुछ क्षतिग्रस्त हो गए। इनकी जगह नये नल लगाए गए और प्रयास हो रहे हैं कि नल घर के अंदर ही लगें ताकि सुरक्षित रहें। नलों में चाहे पानी टंकी से आ जाए, पर गांव के जल-स्रोतों की रक्षा करना और जल संरक्षण कार्य करते रहना बहुत जरूरी है। अतः यहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांववासियों को प्रेरित किया कि टूट-फूट गए एक चेक डैम की भली-भांति मरम्मत कर दी जाए। इसमें श्रमदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब आगे एक और तालाब को बेहतर करने की योजना है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि पंचायत और ठेकेदार में या किसी अन्य स्तर पर कभी-कभी विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं, पर हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी समुदाय के सदस्यों के प्रति बनी रहेगी।

यहां के लोगों ने बताया कि लगभग 80 प्रतिशत परिवारों के शौचालय उपयोग हो रहे हैं, पर कुछ दलित परिवारों के लिए अभी शौचालय नहीं बने हैं। कुछ शौचालयों का प्रयोग पहले नहीं होता था, पर नल में पानी आने के बाद होने लगा। दूसरी ओर ऐसे भी गांव हैं जहां अभी पानी का इंतजार ही हो रहा है। टीकमगढ़ जिले (मध्य प्रदेश) के मोहनगढ़ ब्लॉक का खाकरौन गांव ऐसा ही गांव है। जिला और ब्लॉक मुख्यालय से अधिक दूरी पर स्थित ऐसे गांवों को अधिक इंतजार करना पड़ रहा है। ललितपुर जिले (उत्तर प्रदेश) के विजयपुरा गांव (तालबेहट ब्लॉक) की स्थिति अधिक चिंतित है। यहां तो टैंक बहुत पहले बन गया, नल लग गए थे पर बस ट्रायल का पानी आया, पर उसके बाद गायब हो गया। बन्होरी गांव (जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश) के नरैनी नाले पर लोगों के सामूहिक प्रयास और मनरेगा के आधार पर एक चेक डैम बना है, जिससे 50 से 60 एकड़ की सिंचाई में मदद की और बहुत सुनसान, उपेक्षित क्षेत्र को अच्छी उत्पादकता वाला क्षेत्र बना दिया। बाद में अधिक पानी की जरूरत पड़ने पर इसकी हेडवाल को और बढ़ाया गया। सिंचाई के साथ यहां मछली-पालन भी हो रहा है। आसपास का जल-स्तर भी बढ़ रहा है, कुओं में बेहतर मात्रा पानी उपलब्ध है।

टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ ब्लॉक के एक दूर के क्षेत्र के सात गांवों (जैसे खाकरौन, बरेठी, अनवां आदि) में नाबार्ड की एक वाटरशेड परियोजना का कार्य हो रहा है। इसमें 'रिज से वैली' सिद्धांत के अनुसार मिट्टी और जल संरक्षण, वृक्षारोपण आदि के कार्य हो रहे हैं। खेत-तालाब बनाना, चैक और गैबियन आदि के माध्यम से नदी-नालों पर जल-संरक्षण कार्य इस परियोजना के अंतर्गत हो रहे हैं। आगे इसमें आजीविका और सामुदायिक विकास के अन्य कार्य भी जुड़ते जाएंगे। अभी इसमें कुछ ही कार्य हुआ है पर इसके भी काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। कुओं में जल-स्तर ऊपर आते देखा जा सकता है। उम्मीद है कि इसमें जल-स्तर के सुधार से काफी मदद मिलेगी जिसकी बहुत जरूरत है। खाकरौन गांव के लोगों ने बताया कि दो दशक में यहां जल-स्तर बहुत नीचे गया था पर बारगी नदी और दो नालों में जो जल संरक्षण कार्य हुआ है तो अब यह क्षति रुकी है और जल स्तर ऊपर आने लगा है। लोगों में उत्साह है। प्रमोद नामक किसान ने बताया है कि उसके पास कम भूमि है तो भी उसने अपने खेत में तालाब बनाया है क्योंकि जल-संरक्षण बहुत जरूरी है। गांववासियों ने बताया कि वाटरशेड के विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी अच्छी भागीदारी प्राप्त की जाती है। सागर जिले में बेहतर वाटरशेड विकास देखने के लिए कुछ गांववासियों को ले जाया गया तो वहां से भी अच्छी सीख लेकर आए। जल संरक्षण की दृष्टि से नदी पुनर्जीवन के कार्यों में सबसे अधिक उत्साह नजर आ रहा है।

बरुआ नदी तालबेहट प्रखंड (ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश) में 16 किमी. तक बहने वाली नदी है जो आगे जामनी नदी में मिलती है। इस पर पहले बना चेक डैम टूट-फूट गया था और खनन माफिया ने अधिक बालू निकालकर भी इस नदी की बहुत क्षति की थी। इस स्थिति में परमार्थ संस्था की ओर से इस नदी की रक्षा के लिए विमर्श होता रहा, नदी पर यात्रा निकाली गई, इसकी रक्षा की समिति का गठन हुआ। नया चेक डैम बनाने के पर्याप्त संसाधन न होने के कारण यहां रेत भरी बोरियों का चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया। लगभग 5000 बोरियां एक संस्था ने उपलब्ध करवाईं। इन्हें गांववासियों विशेषकर विजयपुरा की महिलाओं ने रेत से भरा और फिर इसे गांववासी नदी तक ले गए और वहां विशेष तरह से जमाया।

इस तरह बिना किसी मजदूरी या बड़े बजट के अपनी मेहनत के बल पर बोरियों का चेक डैम बनाया। इससे सैकड़ों किसानों को बेहतर सिंचाई प्राप्त हुई। गांव का, कुओं का जल-स्तर भी बढ़ा। गांववासियों और विशेषकर महिलाओं ने खनन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रशासन से संपर्क किया और इस बारे में कार्रवाई भी हुई। आपसी सहयोग से हजारों पेड़ नदी के आसपास लगाए गए। नदी में कोई गंदगी या कूड़ा डालने के विरुद्ध अभियान चलाया गया। मोहनगढ़ ब्लॉक में बहने वाली बारगी नदी को नया जीवन देने में हाल के हुए जल-संरक्षण कार्यों से सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त छतरपुर जिले (मध्य प्रदेश) में काठेड़ी नदी के पुनर्जीवन के भी कुछ उल्लेखनीय प्रयास हाल के समय में हुए हैं, जिनमें प्रशासन, संस्था और पंचायत का सहयोग देखा गया। चेक डैमों की मरम्मत हुई, नये चेक डैम बनाए गए और वृक्षारोपण भी हुआ।

बरुआ नदी तालबेहट प्रखंड (ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश) में 16 किमी. तक बहने वाली नदी है जो आगे जामनी नदी में मिलती है। इस पर पहले बना चेक डैम टूट-फूट गया था और खनन माफिया ने अधिक बालू निकाल कर भी इस नदी की बहुत क्षति की थी। इस स्थिति में परमार्थ संस्था की ओर से इस नदी की रक्षा के लिए विमर्श होता रहा, नदी पर यात्रा निकाली गई, इसकी रक्षा की समिति का गठन हुआ। नया चेक डैम बनाने के पर्याप्त संसाधन न होने के कारण यहां रेत भरी बोरियों का चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया। लगभग 5000 बोरियां एक संस्था ने उपलब्ध करवाई। इन्हें गांववासियों विशेषकर विजयपुरा की महिलाओं ने रेत से भरा और फिर इसे गांववासी नदी तक ले गए और वहां विशेष तरह से जमाया। इस तरह बिना किसी मजदूरी या बड़े बजट के अपनी मेहनत के बल पर बोरियों का चेक डैम बनाया

Dainik Jagran - 28- January-2024

पांच वर्ष में मात्र 80 एमजीडी पेयजल बढ़ा

राजधानी में 1,300 एमजीडी पानी की जरूरत, पानी वितरण को तर्कसंगत बनाने के लिए की कटौती

संतोष कुमार सिंह • नई दिल्ली

दिल्ली में बढ़ रही जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। दिल्ली के पास पानी का अपना स्त्रोत नहीं है। पड़ोसी राज्यों से प्राप्त पानी से दिल्लीवासियों की प्यास बुझती है। पानी की उपलब्धता बढ़ाने और बर्बादी रोकने के प्रयास करते हैं। इसका अब तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। न तो पानी की उपलब्धता में अधिक वृद्धि हुई है और न बर्बादी रोकने में सफलता। पिछले पांच वर्षों में मात्र 80 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पेयजल की बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या 2.15 करोड़ है। दिल्ली जल बोर्ड का दावा है कि 93.5 प्रतिशत क्षेत्र में नल से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पिछले वर्षों में पानी कनेक्शन की संख्या बढ़ी है, परंतु पानी की उपलब्धता नहीं बढ़ी है। इस कारण कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस कारण पानी वितरण को तर्कसंगत बनाने के नाम पर प्रति व्यक्ति पानी आपूर्ति में कटौती किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में दिल्ली में प्रति व्यक्ति 60 जीपीसीडी (गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) पानी आपूर्ति निर्धारित की गई थी। अब इसे 50 जीपीसीडी कर दिया गया है।

93.5 प्रतिशत क्षेत्र में नल के माध्यम से पेयजल दिल्ली में उपलब्ध कराया जा रहा है

60 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में तय हुई थी

राजधानी दिल्ली में पिछले वर्ष पानी कनेक्शन की संख्या बढ़ी है, परंतु पानी की उपलब्धता नहीं बढ़ी है, वजीराबाद संयंत्र में इस वर्ष प्रतिदिन 122.89 एमजीडी पानी हुआ शोधित • जागरण

दिल्ली में जल शोधन संयंत्रों की क्षमता (मिलियन गैलन प्रतिदिन)

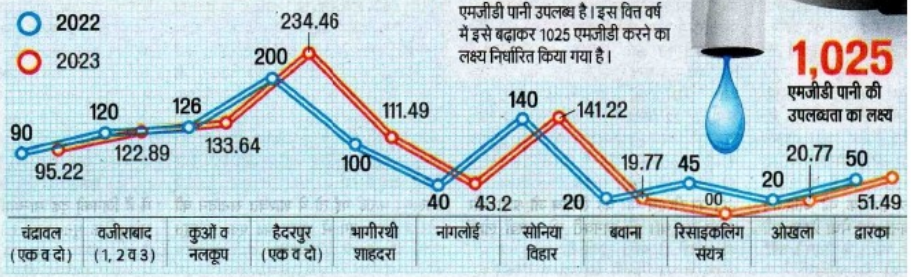

चंद्रावल (एक व दो) | वजीराबाद (1, 2 व 3) | कुओं व नलकूप | हैदरपुर (एक व दो) | भागीरथी शाहदरा | नांगलोई | सोनिया विहार | बवाना | रिसाइकलिंग संयंत्र | ओखला | द्वारका

बरसाती कुओं और नलकूप से बढ़ाई जा रही है उपलब्धता

बरसाती कुओं व नलकूप से पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। पल्ला सहित यमुना डूब क्षेत्र व अन्य स्थानों पर बरसाती कुओं व नलकूप की संख्या बढ़ाने के लिए इस वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पिछले वर्ष तक 5,038 नलकूप लग गए, जिसकी संख्या इस वित्त वर्ष में 54 सौ और बरसाती कुओं की संख्या 10 से 12 की जाएगी। इनके माध्यम से पानी उपलब्धता डेढ़ सौ एमजीडी करने का लक्ष्य है।

दिल्ली जल बोर्ड को विभिन्न स्रोत से उपलब्ध पानी (एमजीडी)

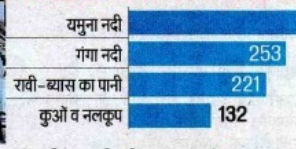

दिल्ली में पानी की जरूरत और उपलब्धता

राजधानी में लगभग 13 सौ एमजीडी पानी की जरूरत है। इसकी तुलना में यमुना, गंग नहर सहित अन्य स्त्रोतों से 995 एमजीडी पानी उपलब्ध है। इस वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर 1025 एमजीडी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

1,025 एमजीडी पानी की उपलब्धता का लक्ष्य

The Times of India - 28- January-2024

As weeds choke Kerala's waterways, women turn hyacinth into handloom

Sreemol.TC@timesgroup.com

Kochi: Ever since the water hyacinth, an invasive plant species, made its appearance in the expansive backwaters of Kerala, scientists have been trying various measures to get rid of the menace blocking the inland waterways of the state. A group of 70 women based in Kodungallur has now made this possible by making products from the processed blades of water hyacinth (Eichornia crassipes) stems collected from waterbodies choked with weeds. Through this unique initiative, the plant has found a new place in showrooms and boutique shops after it was recast as bags, purses, flowerpots, tablemats, cushion covers and other utility products.

The women's group includes differently-abled persons and is part of Kottappuram Integrated Developed Society which facilitated the venture. They collect the long stems of the weed from the stagnant water, dry it, remove the piths after peeling the stem, dye it and weave it in the loom to make products which have good takers. Apart from their own retail outlets, the women display these at exhibitions and sell them through B2B online marketing.

A group of 70 women is recasting the invasive water hyacinth into products such as bags, purses, flowerpots, tablemats, cushion covers and other utility products

Valsala Prasad, a senior artisan in the firm, said they need blades of at least 200 stems to make a bag on which designs are made by weaving cotton. "We peel the stem into three blades and remove the pith using a knife before drying and dyeing it. I need one day to make a bag," she added.

"The water hyacinth reached Kerala as a garden plant. It later entered waterbodies. Many places where people used to cultivate paddy near the inland waterways stopped it many years ago, making the area suitable for the growth of the hyacinth. Later, it entered the inland waterways. Since the weed has a long root system, it prevents the flow of water and thereby accumulates the waste and debris," said Prabhakaran, assistant professor of Fisheries and Ocean Studies at Kerala University.

Fr Paul Thomas, the firm's director, urged government to support the group so it can make new products. "Currently, we use only its stem. We are looking at how we can make by-products like fabric out of its leaves."